

दिनांक 30 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/10९-८६/४५६७.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० के० जी० ज्ञोसक्ता कम्प्रे शर्जे लि०, 18.८-कि० मि०, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जयपाल सिंह मार्फत श्री शामसुन्दर गुप्ता, ५० नीलम चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांगलीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शब्दियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-(३)-श्रम ६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९७८ के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-श्रम ५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के प्रयोग गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे तिना मानना न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रमिक विवाद सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जयपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 28 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/पानी०/७३-८६/४१४९.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (१) प्रबन्धक निदेशक, एच-एस-एम, श्री ई. टी. सो. हरियाणा, चण्डीगढ़, (२) कार्यकारी अभियन्ता, फील्ड डिविजन, एच. एस. एम. श्री ई. टी. सी. थर्मल पावर आसन, ४ गोले हे प्रेस हाउस एवं इन्डस्ट्रीज, युनियन गोले, गोला तथा उसने प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

श्री ई. टी. सो. हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांगलीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शब्दियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ३ (४४)८४-३-श्रम, दिनांक १८ अप्रैल, १९८४ द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे तिना मानना न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रमिक विवाद सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजेंद्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि०/एफ०डी०/६४-८५/४०९०.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ईलाईट सैरामिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० १६१, सैक्टर-२४, फरीदाबाद के श्रमिक श्री मंगल मार्फत अन्तर्राष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन, जी-१६२, इन्ड्रानगर सैक्टर ७, फरीदाबाद तथा उसने प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांगलीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शब्दियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-श्रम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९७८ के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-श्रम ५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे तिना मानना न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रमिक विवाद सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मंगल की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं नीर हाजिर रह गये नोटों से धूर्दामावितार (लिशन) खोया है ? इस त्रिकुप पर निर्गम के कर्तव्यहृत वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/६४-८५/४०९७.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ईलाईट सैरामिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० १६१, सैक्टर-२४, फरीदाबाद के श्रमिक श्री भूमि प्रसाद, मार्फत अन्तर्राष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन जी-१६२,

इन्हा नगर, सैकटर-7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है ;

ग्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस सिये, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

यथा श्री भूमी प्रसाद की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर रह कर नौकरी से पुर्णग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/एफ.डी./64-85/4104.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ईलाईट सेरामिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 161, सैकटर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ननका, मार्पत आनंदराई रुद्रा रुद्रिन जी-१६२, इन्द्रा नगर, सैकटर-7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है ;

ग्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इससिये, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

यथा श्री ननका की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर रह कर नौकरी से पुर्णग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/एफ.डी./64-85/4111.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ईलाईट सेरामिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 161, सैकटर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रेवा मार्फत अन्तराइप्रोफार्म मजदूर यूनियन जी-१६२, इन्द्रा नगर, सैकटर-7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है ;

ग्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इससिये, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

यथा श्री रेवा की सेवा समाप्त की गई है या उसने दृथ रैर हाजिर रह कर नौकरी से पुर्णग्रहण दिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के पल्लरद्वरूप वह विस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/पानीपत/62-86/4120.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य किल्ली बोर्ड, चंडीगढ़ (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन हरियाणा राज्य डिजली बोर्ड, करनाल, वे श्रमिक श्री मोहन सिंह, पुत्र श्री सुमेर सिंह, गांव व डा० खेड़ी नारू, तह० करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले कोई श्रीदोगिक विवाद है ;

ग्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इति०१८. प्रा० श्रीदोगिक विवाद नियमान्वयन, १९६२ की विधा० (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ३(४)८४-३-श्रम, दिनांक १८ अगस्त,

1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला, को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मोहिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि�०/पानीपत/3-87/4128.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी करनाल सण्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, दी माल करनाल, के अभिक श्री सतवीर सिंह, पुत्र श्री रघवीर सिंह, दीनानाथ चिर्लिंग, नजदीक फूड सप्लाई एफाफिस, अम्बाला शहर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीये गिर्विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा देना की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सतवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि�०/पानीपत/1-87/4135.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कार्यकारी अधियक्ता, हुड़ा नज़री डिवीज़नेट अग्राही, करनाल, अखेर इस्टेट, करनाल के अभिक श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री राम चन्द शर्मा, गांव नह खेड़ी, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीयोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सतीश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि�०/पानीपत/72-86/4142.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) प्रबन्धक निवेशक, एच० एस० एम० आई० टी० सी०, हरियाणा, चाहीगढ़ (2) कार्यकारी अधियक्ता, फैल्ड विविजन, एच०एस०एम०आई०टी०सी०, धर्मनगर आसन, पानीपत के अभिक श्री जयपाल, पुत्र श्री जाये राम, गांव व डांगुडा, तह० व जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीयोगिक विवाद है, —

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला, को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?